PRGI. No.: MHMUL/25/A2419

प्यूपिल्स टाइम्स

PUPILS TIMES

Volume : 1 ‣ Issue : 2 ‣ Mumbai ‣ Friday, 13 February to 19 February 2026 ‣ Weekly ‣ Pages: 8 ‣ Price : 3 Rs.

मुंबई महानगरपालिका में नई महापौर-उपमहापौर की ताजपोशी

रितु तावड़े महापौर और संजय घाड़ी को उपमहापौर की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस-उपमुख्यमंत्री शिंदे ने किया स्वागत

मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिका के महापौर पद पर भारतीय जनता पार्टी की नगरसेविका रितु तावड़े और उपमहापौर पद

पर शिवसेना के संजय घाड़ी का चयन किया गया। बुधवार को इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दोनों को पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महापौर, उपमहापौर और सभी पदाधिकारी मिलकर महानगरपालिका को सही दिशा देंगे और आम मुंबईकरों के सपनों को साकार करने का कार्य करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उन्हें पूर्ण सहयोग देगी और उनके माध्यम से 'नई मुंबई' के निर्माण को गति दी जाएगी। महानगरपालिका सभागृह में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रितु तावड़े को एक अनुभवी और सशक्त मराठी नेतृत्व के रूप में देखा जाता है। उन्होंने पहले भी मुंबईकरों के मुद्दों पर

आक्रामक भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में महायुति सरकार द्वारा शुरू किए गए मुंबई विकास कार्यक्रमों को महानगरपालिका के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उपमहापौर संजय घाड़ी के अनुभव का भी निगम को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासक व्यवस्था समाप्त होकर लोकप्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होना खुशी की बात है, क्योंकि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अधिक जुड़ाव महसूस करती है।

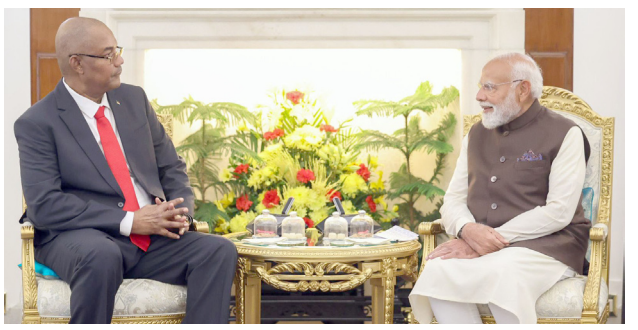

पीएम मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी से मुलाकात की

नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मुलाकात की। इससे पहले सेशेल्स के राष्ट्रपति ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सोमवार को इससे पहले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मुलाकात की और विजन महासागर के लिए राष्ट्रपति के समर्थन की सराहना की। राष्ट्रपति हर्मिनी भारत की अपनी चल रही राजकीय यात्रा के तहत चेन्नई और मुंबई में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद रविवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। उनकी यह यात्रा, जो 10 फरवरी तक चलेगी, अक्टूबर 2025 में पदभार संभालने के बाद से भारत की उनकी पहली यात्रा है और यह भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उत्सव के साथ मेल खाती है। विदेश मंत्रालय द्वारा पर प्रकाशित एक पोस्ट के अनुसार, चेन्नई और मुंबई में अपने दौरों के दौरान, हर्मिनी ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए शासन, उद्योग, तटीय प्रबंधन और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों से मुलाकात की।

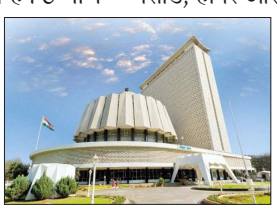

राज्य का बजट सेशन 23 फरवरी से; 6 मार्च को बजट

मुंबई - मुंबई में होने वाला राज्य विधानसभा का बजट सेशन सोमवार, 23 फरवरी से बुधवार, 25 मार्च, 2026 तक तय किया गया है। 6 मार्च को बजट पेश करने का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लिया गया।

विधान भवन में लेजिस्लेटिव बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन प्रो. राम शिंदे, लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर एडवोकेट राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार, लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिप्टी चेयरमैन डॉ. नीलम गोरहे, लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर अन्ना बंसोडे, हायर और टेक्निकल एजुकेशन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर चंद्रकांतदादा पाटिल, रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले, कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर एडवोकेट शामिल हुए। आशीष शेलार, टछअ सर्वश्री अनिल परब, प्रसाद लाड, भास्कर जाधव, जयंत पाटिल, सुनील प्रभु, भाई जगताप, प्रवीण दारकेकर, विक्रम काले, सतेज पाटिल, विधानसभा के सेक्रेटरी जितेंद्र भोले और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

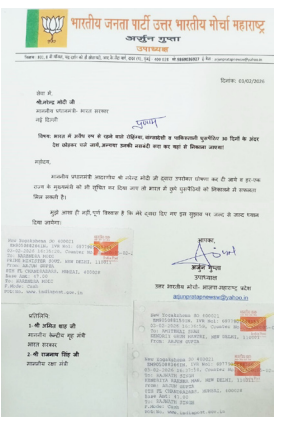

अवैध घुसपैठियों पर कठोर कारवाई करें

भाजपा नेता अर्जुन गुप्ता ने की कार्रवाई मांग

भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र
अर्जुन गुप्ता
उपाध्यक्ष

प्रणाम

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

मुंबई - महाराष्ट्र भाजपा नेता अर्जुन गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह एवं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को पत्र प्रेषित कर भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या तथा पाकिस्तानी नागरिकों के विरुद्ध त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा कर 30 दिवस के भीतर देश त्यागने का निर्देश देने का आग्रह किया है। निर्धारित अवधि के उपरांत जो भी अवैध रूप से निवास करते पाए जाएँ, उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही सभी मुख्यमंत्रियों को समन्वित रूप से दृढ़ कदम उठाने का निवेदन किया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि-व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे।

मुंबई में लाखों रुपए मूल्य के फर्जी स्टैंप बरामद

शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्य दबोचे गए

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

मुंबई - मुंबई की एमआरए मार्ग पुलिस ने भारतीय डाक विभाग के नाम पर नकली पोस्टल स्टैंप तैयार कर उन्हें विभिन्न राज्यों में बेचने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों के पास से लाखों रुपए मूल्य के फर्जी स्टैंप बरामद किए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 12 सितंबर 2025 को मुंबई जीपीओ के डाक निरीक्षक आशुतोष जमादारसिंह कुमार ने एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि बाजार में बड़ी मात्रा में संदिग्ध डाक टिकट चलन में हैं। पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू कर जीपीओ से जानकारी जुटाई, जिसमें खुलासा हुआ कि गिरोह बड़े पैमाने पर नकली स्टैंप छापकर कूरियर के माध्यम से देशभर में सप्लाई कर रहा था।

जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के बैंक खातों में 7 से 8 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन-देन का पता चला, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर यह भी सामने आया कि इस नेटवर्क के मुख्य संचालक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में छिपे हुए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने मोबाइल नंबर और ठिकाने बदल रहे थे।

मुंबई पुलिस की टीम ने दिल्ली में 14 दिनों तक रहकर मुखबिर से सूचनाएं जुटाईं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में कुल 27,84,200 रुपए मूल्य के नकली पोस्टल स्टैंप जब्त किए गए।

प्यूपिल्स टाइम्स

संपादकीय

डिजिटल प्लेटफार्मों की बढ़ी जवाबदेही..!

भारत का डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। मशीनी कौशल (एआइ) में हुई प्रगति, खासकर आडियो, वीडियो और आडियो-वीडियो कंटेंट को बनाने और बदलने की तकनीक ने सूचना के सृजन, उपभोग और विश्वास के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। जहां ये तकनीक अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और लोगों तक पहुंच को बढ़ाती हैं, वहीं ये ऐसे नए खतरे भी पैदा करती हैं जो सीधे तौर पर व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं। कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी से पैदा होने वाली खास चुनौतियों को समझते हुए भारत सरकार ने डिजिटल मध्यस्थों (डिजिटल इंटरमीडियरी) से जुड़े कानून और नीतिगत ढांचे को और मजबूत किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 में किए गए हालिया संशोधन और नवंबर 2025 में इंडिया एआइ मिशन के तहत जारी भारत की एआइ गवर्नेंस गाइडलाइंस, 2025-दोनों को साथ पढ़ने पर सरकार का एक संतुलित और स्पष्ट दृष्टिकोण सामने आता है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक नुकसान से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी जिम्मेदारियां तय की गई हैं और साथ ही जिम्मेदार तरीके से एआइ को अपनाने के लिए नीतिगत सिद्धांत भी तय किए गए हैं।

हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए ये सभी नियम और दिशानिर्देश मिलकर सरकार की एक साफ मंशा दिखाते हैं-तकनीक का विकास ऐसा हो, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक की गरिमा को बनाए रखने वाले ढांचे के भीतर ही आगे बढ़े। संशोधित इंटरमीडियरी नियमों में पहली बार कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी की एक साफ और व्यावहारिक परिभाषा दी गई है। इसमें वह कंटेंट शामिल है जो इस तरह बनाया या बदला गया हो कि वह असली जैसा लगे या हकीकत से अलग पहचान में न आए, लेकिन इसमें सामान्य और ईमानदार कामों को साफ तौर पर बाहर रखा गया है-जैसे तकनीकी एडिटिंग, दिव्यांगों की सुविधा के लिए किए गए बदलाव, पढ़ाई या शोध से जुड़ी सामग्री और वैध रचनात्मक उपयोग।

इससे यह सुनिश्चित होता है कि डिजिटल नुकसान के नए तरीकों से मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर ही निपटा जाए, न कि उसे अनौपचारिक या प्लेटफार्म की अपनी माडरेशन व्यवस्था पर छोड़ दिया जाए। इतना ही महत्वपूर्ण यह स्पष्टीकरण है कि मध्यस्थों द्वारा स्वचालित उपकरणों या अन्य उचित तकनीकी उपायों के माध्यम से सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाइयां वैधानिक सुरक्षा को कमजोर नहीं करती हैं।

थूकने पर 250, कूड़ा फैलाने 500

मुंबई मनपा लगाएगी 25000 हजार रुपये तक जुर्माना

मुंबई - मुंबई में नए मेयर की ताजपोशी से पहले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने शहर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से कड़े नियम जारी कर दिए हैं। बीएमसी की नए ठोस कचरा प्रबंधन उपविधि 2025 के तहत कचरा और गंदगी फेंकने पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। बीएमसी ने ठोस कचरा के प्रबंधन एवं हैंडलिंग के साफ-सफाई करने के लिए उल्लंधन पर लोगों और विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। बीएमसी के अनुसार पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 250 रुपये, कचरा फेंकने पर 500 रुपये वूसले जाएंगे। गौरतलब हो कि बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगरपालिका है।

बीएमसी ने कहा है कि अगर कोई गीले और सूखे कचरे का वर्गीकरण नहीं करता है तो उसे 200 रुपये जुर्माने के तौर देने पड़ेंगे। बिना अनुमति निर्माण और ध्वस्तीकरण मलबे के परिवहन पर 25 हजार रुपये प्रति वाहन का जुर्माना लगेगा। बीएमसी के प्रशासक भूषण गगराणी के निर्देशों के अनुसार मुंबई को स्वच्छ रखने के लिए ये नियम लागू किए गए हैं। बीएमसी के अनुससर ये नियम कचरा उत्पन्न करने वाले सभी व्यक्तियों और स्थानों, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, पर लागू होंगे। इनमें आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, सरकारी, अर्ध-सरकारी, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के परिसर पर लागू होंगे।

बीएमसी ने साफ किया है कि अगर नगर निगम के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद 4 घंटे के भीतर सफाई नहीं सुनिश्चित की गई तो जमा की स्वच्छता राशि जब्त की जाएगी। बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि कुल 21 प्रकार के उल्लंघनों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बीएमसी चुनावों के बाद बीजेपी के कई पार्षदों ने जुलूस निकालने के बाद साफ-सफाई करके अपनी तस्वीर पोस्ट की थी।

महाराष्ट्र ने लाड़की बहिण योजना के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ाई

मुंबई - मुख्यमंत्री लाड़की बहिण योजना के कम से कम 25 लाख लाभार्थियों ने राहत की सांस ली है क्योंकि राज्य सरकार ने ऑनलाइन सत्यापन के दौरान गलत जवाब देने वालों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।

इन लाभार्थियों को पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान गलत उत्तर देने के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया था। पूर्व समय सीमा 31 दिसंबर, 2025 थी, जिसके बाद ऑनलाइन प्रश्न के गलत उत्तर के कारण 25 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों को लाभ से वंचित होना पड़ा। आवेदन की समय सीमा अब बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, जिससे लाभार्थियों को पात्रता से संबंधित मुख्य प्रश्न के उत्तर को सही करने का अवसर मिलेगाः लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी विभाग, उपक्रम, बोर्ड या स्थानीय प्राधिकरण में नियमित, स्थायी या संविदा कर्मचारी नहीं होना चाहिए; या क्या ऐसा कोई सदस्य सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है जो

पेंशन प्राप्त कर रहा है - हाँ या ना।

पहले यह बात सामने आई थी कि बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने गलती से गलत विकल्प चुन लिया था और परिणामस्वरूप उन्हें लाभ नहीं मिला। समय सीमा बीत जाने के बाद जब लाभार्थियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उनमें से कई ने सुधार के लिए सरकार से संपर्क किया। राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से शारीरिक सत्यापन कराने का पूर्व निर्णय विफल हो गया, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने अपने नियमित कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपे जाने का विरोध किया था।

सरकार ने अब ऑनलाइन सुधार प्रक्रिया का विकल्प चुना है, जिससे लाभार्थियों को अपने उत्तरों में संशोधन करने की अनुमति मिलेगी। 24 जुलाई, 2024 को शुरू की गई लड़की बहन योजना सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के लिए राजनीतिक लाभ के मामले में निर्णायक साबित हुई है। पात्रता मानदंडों में बदलाव के बाद, शुरूआती लाभार्थियों की संख्या 2.43 करोड़ से घटकर अब 1.88 करोड़ रह गई है।

35 साल के मेंटेनेंस के साथ आएगी वंदे मेट्रो लोकल

प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, प्री-बिड मीटिंग पूरी

मुंबई - मुंबई की उपनगरीय रेल व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम हासिल हुआ है। मुंबई रेल विकास कारपोरेशन (एमआरवीसी) की ओर से प्रस्तावित 238 वंदे मेट्रो एसी लोकल ट्रेनों के लिए टेंडर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और अब तक दो महत्वपूर्ण प्री-बिड मीटिंग सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं। अधिकारी के अनुसार परियोजना तय समय-सारिणी के अनुरूप चल रही है और तकनीकी व कमर्शियल पहलुओं पर कंपनियों को आवश्यक स्पष्टता दे दी गई है।

दरअसल यह महत्वाकांक्षी योजना मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट परियोजना फेज-III और III-अ के अंतर्गत लागू की जा रही है। इसके तहत मुंबई के लिए नई पीढ़ी की वंदे मेट्रो एसी लोकल ट्रेनों का निर्माण होगा। जो आधुनिक तकनीक और बेहतर यात्री सुविधा पर आधारित होंगी। निविदा में ट्रेन सेट की सप्लाई के साथ 35 वर्षों की लाइफ-टाइम मेंटेनेंस व्यवस्था भी शामिल है। इससे ट्रेनों की विश्वसनीयता और सेवा उपलब्धता लंबे समय तक सुनिश्चित की जा सकेगी।

एमआरवीसी का कहना है कि प्री-बिड बैठकों में उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी रही और अधिकांश तकनीकी सवालों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। इसी वजह से बोली प्रक्रिया में किसी बड़ी देरी की संभावना नहीं है। योजना के मुताबिक, पहला प्रोटोटाइप ट्रेन सेट करीब ढाई साल में तैयार हो सकता है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर ट्रेनों की आपूर्ति शुरू होगी। यह परियोजना मुंबई की लोकल सेवाओं को क्षमता, आराम और तकनीक के नए स्तर तक ले जाने वाली मानी जा रही है।

आओ खेलें

	8	6	7	4	5	E		F	C				9	1	
		3		2		C	A	5			1	6	G		
			C		F	9	D	8		B	6	E	A		
	D	1	A		B			E							C
E		F			4				G	3		C	7	8	
		B	3	9			7	C	E	6	A	2	4	5	
C	G	2	5	6		3			8				D	A	F
		7	4			G		9		D	F				1
	A	E				1		D		F	4		C		5
	5	4	F	D	C			3		G	B		6	9	E
6	7		G			5			9	C	E	A		B	D
	B	C	9				6		1					F	
F		G			6				A	2					
4				5						8		1		7	
	E	D		C		4		7	F	1		G	3		
			1	G		D	F				5	B		C	4

प्यूपिल्स टाइम्स

वैश्विक बाजार में पहचान बनाने का मौका

नई दिल्ली - भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस समझौते का प्रारूप अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश कर दिया गया है, जिससे किसी भी तरह के भ्रम या आशंका की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश के हितों की, विशेष रूप से कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों की, पूरी सतर्कता और मजबूती के साथ रक्षा की है। सुधांशु त्रिवेदी ने आम बोलचाल की भाषा में समझाते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों को इस व्यापार समझौते के तहत सुरक्षित या संरक्षित रखा गया है, उन पर किसी भी प्रकार के विदेशी आयात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल, मिलेट्स सहित कई अहम कृषि उत्पादों की विस्तृत सूची शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार ने किसानों के हितों का दृढ़ता के साथ संरक्षण किया है। साथ ही देश के दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों के हितों की भी पूरी तरह रक्षा की गई है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इस व्यापार समझौते के जरिए देश के लघु और मध्यम उद्योगों के उद्यमियों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए गए हैं। उन्होंने इसे देश के लिए एक बड़ा अवसर बताते हुए कहा कि भारतीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा।

अब वाहन चालकों को सुनाई देगा 'जय हो' गाना

मुंबई में लोगों को मिलेगा म्यूजिकल सफर का अनुभव

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

मुंबई - मुंबई की सड़कों पर अब सिर्फ ट्रैफिक की आवाज नहीं, बल्कि संगीत की मधुर धुन भी सुनाई देगी. मुंबई कोस्टल रोड (धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज तटीय मार्ग) के नाम से जाना जाता है. अब एक नए और अनोखे अनुभव के लिए तैयार है. इस मार्ग पर भारत का पहला म्यूजिकल रोड (मेलोडी रोड) बनाया गया है. जहां गाड़ियां गुजरते ही ऑस्कर विनिंग गाना 'जय हो' सुनाई देगा.

इस खास म्यूजिकल रोड का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बुधवार (11 फरवरी) दोपहर 12:30 बजे किया जाएगा. यह सुविधा नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाली लेन पर शुरू की जा रही है. जहां सड़क पर विशेष तकनीक से बनी म्यूजिक स्ट्रिप्स लगाई गई हैं.

जानकारी के अनुसार, इन स्ट्रिप्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब वाहन एक तय गति से इनके ऊपर से गुजरते हैं, तो पहियों के कंपन से संगीत की धुन निकलती है. इसी तकनीक के जरिए अब वाहन चालकों को फिल्म 'स्लमडॉग मिलेनियर' का मशहूर गीत 'जय हो' सुनाई देगा, जो पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन चुका है.

यह प्रयोग न सिर्फ तकनीकी रूप से खास है, बल्कि यात्रियों के अनुभव को भी नया और आनंददायक बनाने वाला है. मुंबई कोस्टल रोड पहले से ही ट्रैफिक जाम से राहत, तेज यात्रा और सुंदर समुद्री नजारों के लिए जाना जाता है और अब इसमें संगीत का रंग भी जुड़ गया है.

लोगों को यात्रा के दौरान मिलेगा एक यादगार और खुशहाल अनुभव खास बात यह है कि यह दुनिया का पांचवां म्यूजिकल रोड है, लेकिन भारत का पहला ऐसा प्रयोग है. इससे मुंबई न सिर्फ स्मार्ट सिटी की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रही है. बल्कि लोगों को यात्रा के दौरान एक यादगार और खुशहाल अनुभव भी दे रही है.

अब मुंबई में अपना घर खरीदने का सपना होगा पूरा

- म्हाडा की 120 फ्लैट्स की लॉटरी,
- पहले आओ पहले पाओ से मौका

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

मुंबई - मुंबई में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे मुंबईकरों के लिए गुड न्यूज है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुंबई के अलग-अलग इलाकों में 120 फ्लैट्स बेचने का ऐलान किया। इस स्कीम की खासियत यह है कि ये घर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक, इन घरों की कीमतें अक्सर बदलती रहती हैं। साउथ मुंबई के ताड़देव में सबसे महंगे अपार्टमेंट की कीमत 8 करोड़ से ज्यादा है। जबकि सबसे सस्ते घर की कीमत 38 लाख है।

म्हाडा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, ये फ्लैट्स मुंबई के कई जरूरी इलाकों जैसे कांदिवली, चारकोप, वडाला, पवई, ताड़देव, जुहू और अंधेरी में हैं। इन फ्लैट्स के लिए लॉटरी कुछ दिन पहले हुई थी। लेकिन किसी वजह से यह फ्लैट नहीं बिका। अब इन्हें 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बिक्री के लिए रखा गया है। इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन गुरुवार, 5 फरवरी, 2025 को म्हाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो गया है। इसके बाद, एप्लीकेंट अपनी पसंद का फ्लैट चुन सकते हैं और 12 फरवरी, 2026 से सिक्योरिटी डिपॉजिट और एप्लीकेशन फीस दे सकते हैं। वेबसाइट पर फ्लैट चुनने के बाद आपको 48 घंटे के अंदर घर की कुल कीमत का 10 परसेंट जमा करना होगा। यह पेमेंट मिलने पर म्हाडा आपको बाकी रकम के लिए एक प्रोविजनल 'ऑफर लेटर' जारी करेगा। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आप 48 घंटे के अंदर यह 10% रकम जमा नहीं करते हैं। तो आपका क्लेम कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी।

म्हाडा ने साफ किया कि अगर कोई एप्लीकेंट 'प्रोविजनल ऑफर लेटर' मिलने के बाद किसी भी वजह से फ्लैट कैंसिल करता है या तय समय के अंदर पूरी कीमत जमा नहीं करता है। फिर फ्लैट की कुल कीमत का 1% पेनल्टी काट ली जाएगी। बाकी रकम बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं, उन्हें अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला प्री-अप्रूवल लेटर अपनी लॉगिन क्ळ से अपलोड करना होगा। उसके बाद म्हाडा उसी लॉगिन क्ळ का इस्तेमाल करके बैंक को एनओसी जारी करेगा। फ्लैट की पूरी कीमत और स्टाम्प ड्यूटी देने के बाद म्हाडा एप्लीकेंट को अलॉटमेंट और पजेशन लेटर जारी करेगा।

अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी रैकेट का किया भंडाफोड़

भारतीय तटरक्षक बल को मिली बड़ी सफलता, मुंबई के पास तीन संदिग्ध जहाजों को पकड़ा, तेल जब्त

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली - भारतीय तटरक्षक बल (आइसीजी) ने एक सुनियोजित समुद्री-हवाई समन्वित अभियान के जरिये एक अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी रैकेट का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है। इस अभियान से संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में तेल और तेल-आधारित कार्गो के अवैध हस्तांतरण में शामिल एक जटिल नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। पांच फरवरी को मुंबई से लगभग 100 समुद्री मील पश्चिम में भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों ने तीन संदिग्ध जहाजों को पकड़ा।

गिरोह में कई देशों में काम करने वाले दलाल शामिल बल की विशेषज्ञ बोर्डिंग टीमें जहाजों की लगातार तलाशी, जहाज पर बरामद इलेक्ट्रानिक डाटा की पुष्टि, दस्तावेजों का सत्यापन और चालक दल के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ के द्वारा

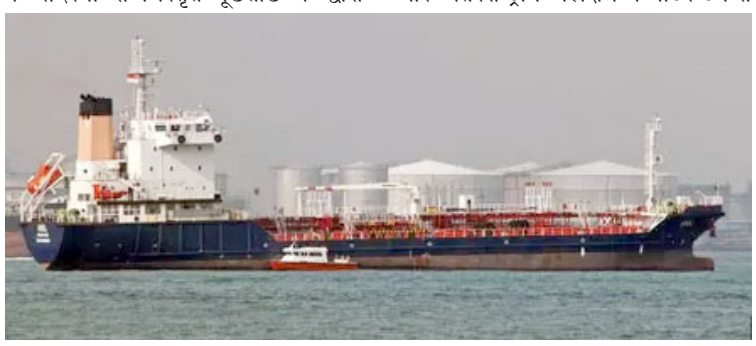

घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटाने और आपराधिक कार्यप्रणाली की पुष्टि कर पाईं। तस्करी करने वाले गिरोह ने एक ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई थी जिसमें सस्ते तेल को समुद्री जहाजों द्वारा ले जाया जाता था और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मोटर टैंकरों में स्थानांतरित किया जाता था।

प्रारंभिक जांच से पता चला कि गिरोह में कई देशों में काम करने वाले दलाल शामिल थे, जो समुद्र में जहाजों के बीच माल की बिक्री और हस्तांतरण कार्य का समन्वय करते थे।

तटीय राज्यों को देय भारी शुल्क की चोरी हो रही थी बल की तकनीक-आधारित निगरानी प्रणालियों द्वारा पता चलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया, जिसमें भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर संदिग्ध गतिविधि में लिप्त एक मोटर टैंकर की पहचान की गई। इसके बाद, जहाजों की आवाजाही की डिजिटल जांच और डाटा पैटर्न विश्लेषण से टैंकर की ओर आ रहे दो अतिरिक्त जहाजों की पहचान हुई, जिन पर अवैध रूप से तेल के जहाज-से-जहाज पर हस्तांतरण में शामिल होने का संदेह था, जिससे भारत सहित तटीय राज्यों को देय भारी शुल्क की चोरी हो रही थी। भौतिक तलाशी लेने पर हुई डिजिटल साक्ष्य की पुष्टि पांच फरवरी को भौतिक तलाशी से डिजिटल साक्ष्य की पुष्टि होने पर तीनों जहाजों को जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए ये जहाज अक्सर अपनी पहचान बदलते रहते थे।

शुरूआती जांच से यह भी पता चलता है कि जहाजों के मालिक विदेश में रहते हैं। जब्त किए गए जहाजों को आगे की जांच के लिए मुंबई ले जाया जाएगा और बाद में उचित कानूनी कार्रवाई के लिए भारतीय सीमा शुल्क और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा।

युवाओं और नाबालिगों में सोशल मीडिया की लत

बच्चों में डिजिटल लत का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टास्क फोर्स नियुक्त करने का आदेश

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली - बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत के उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने इस विषय पर गहन अध्ययन करने और प्रभावी समाधान सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक टास्क फोर्स नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 29 जनवरी, 2026 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26) ने युवाओं और नाबालिगों में सोशल मीडिया की लत के बढ़ते जोखिमों पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर आयु सीमा निर्धारित करने और नाबालिगों को लक्षित डिजिटल विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई है।

इस रिपोर्ट के मद्देनजर, महाराष्ट्र के लिए इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव वीरेंद्र सिंह को विशेषज्ञों की एक टास्क फोर्स नियुक्त करने के लिए लिखित निर्देश दिए गए हैं। शेलार ने बताया कि राज्य में

18 साल से कम उम्र के चार करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से तीन करोड़ 15 साल से कम उम्र के हैं। उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का मुद्दा अहम है।

अपने लेटर में, उन्होंने इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के 77वें सालाना नेशनल कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए नतीजों का भी जिक्र किया। इस कॉन्फ्रेंस से पता चला है कि युवाओं में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में खतरनाक बढ़ोतरी हुई है, और यह साफ हो गया है कि 50 परसेंट से ज्यादा मेंटल बीमारियां 18 साल की उम्र से पहले शुरू होती हैं और 35 साल से कम उम्र के ग्रुप में इन प्रॉब्लम के मामले काफी बढ़ गए हैं। इसलिए, उन्होंने कहा कि बचाव के उपायों की तुरंत जरूरत है।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर एडवोकेट शेलार ने निर्देश दिया है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इस विषय पर पूरी स्टडी करे ताकि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की सिफारिशों और एक्सपर्ट्स द्वारा पेश किए गए नतीजों के आधार पर राज्य के लिए एक बैलेंस्ड और जानकारी वाली पॉलिसी बनाई जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि अगर जरूरी हो तो पूरी स्टडी के लिए एक्सपर्ट्स की एक टास्क फोर्स बनाई जाए।

आर्थिक बहस से नीतिगत स्पष्टता की आवश्यकता

नई दिल्ली - संसद का वर्तमान सत्र देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा का मंच बना है। महंगाई, रोजगार, कर नीति, छोटे उद्योगों की स्थिति और डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा जैसे विषयों पर हुई बहस यह संकेत देती है कि आर्थिक दिशा को लेकर चिंता और अपेक्षा – दोनों मौजूद हैं। लोकतंत्र में यह स्वाभाविक भी है कि सरकार और विपक्ष आर्थिक नीतियों पर अलग-अलग दृष्टिकोण रखें, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि बहस समाधान की ओर बढ़े।

महंगाई आज आम नागरिक की सबसे बड़ी चिंता है। खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन और सेवाओं तक बढ़ती कीमतों ने मध्यम और निम्न आय वर्ग के बजट पर दबाव डाला है। सरकार वैश्विक कारणों और आपूर्ति तंत्र की चुनौतियों का हवाला देती है, जो काफी हद तक सही भी है, पर जनता को तात्कालिक राहत देने के लिए ठोस और लक्षित उपाय आवश्यक हैं। केवल दीर्घकालिक आश्वासन पर्याप्त नहीं – अल्पकालिक सुरक्षा कवच भी जरूरी है। रोजगार का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विकास दर के आंकड़े सकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन यदि रोजगार सृजन समान गति से न बढ़े तो विकास का लाभ व्यापक नहीं हो पाता। कौशल विकास, विनिर्माण और स्टार्टअप क्षेत्र में अवसर बढ़ाने की पहल सराहनीय है, किंतु इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। रोजगार आंकड़ों की पारदर्शिता से विश्वास भी बढ़ेगा।

MSME क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यही क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देता है। आसान ऋण, सरल कर व्यवस्था और कम अनुपालन बोझ – ये तीन कदम छोटे उद्योगों को नई ऊर्जा दे सकते हैं। संसद में इस विषय पर सहमति बनना एक सकारात्मक संकेत है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार भारत की बड़ी उपलब्धि है, पर इसके साथ डिजिटल धोखाधड़ी और डेटा सुरक्षा के खतरे भी बढ़े हैं। उपभोक्ता संरक्षण, साइबर सुरक्षा और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र अब विलासिता नहीं, आवश्यकता हैं। नीति निर्माण को तकनीकी गति के साथ तालमेल रखना होगा।

संसदीय बहस का उद्देश्य केवल आलोचना या बचाव नहीं, बल्कि बेहतर नीति का निर्माण होना चाहिए। यदि सरकार सुझावों को स्वीकारने की उदारता दिखाए और विपक्ष रचनात्मक सहयोग दे, तो आर्थिक चुनौतियाँ अवसर में बदली जा सकती हैं। देश को आज टकराव नहीं, ठोस आर्थिक रोडमैप की जरूरत है।

ओडिशा में 13 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर बीजद ने राज्यपाल से की अपील

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

भुवनेश्वर – ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) ने राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति से राज्य के 13 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की तत्काल नियुक्ति करने का आग्रह किया है।

बीजद के प्रतिनिधिमंडल में बीजू युवा जनता दल और बीजू छात्र जनता दल के सदस्य शामिल थे। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कहा कि विश्वविद्यालयों में नेतृत्व पदों की रिक्तियों के कारण शैक्षणिक और प्रशासनिक स्थिरता प्रभावित हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि नियुक्तियों में योग्यता और निष्पक्षता का पालन होना चाहिए और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता और शैक्षणिक अखंडता सुरक्षित रखी जानी चाहिए। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से चल रही है और जल्द ही इसे पूरा कर दिया जाएगा। बीजद ने चेतावनी दी कि यदि नियुक्तियाँ फरवरी के अंत तक नहीं हुईं, तो वह व्यापक आंदोलन का संकेत दे सकती है।

ओडिशा के कई सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में लंबे समय से नियमित कुलपति नहीं हैं, जिससे परीक्षा-प्रबंधन, शोध और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है। बीजद का कहना है कि पूरे राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित में जल्द निर्णय आवश्यक है।

मनपा लाइसेंसिंग विभाग के दो अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

मुंबई – मुंबई में ब्रिहनमुंबई नगर निगम के लाइसेंसिंग विभाग से जुड़े दो कर्मचारी एंटी करप्शन ब्यूरो की गिरफ्त में आए हैं, जब वे एक कॉफी शॉप मालिक से रु. 35,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए।

घटना जी नॉर्थ वार्ड के लाइसेंसिंग विभाग में तैनात इंस्पेक्टर कविता धनवड़े और सीनियर इंस्पेक्टर सैय्यद इमाम के साथ हुई। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता कैफे मालिक ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों ने उसकी दुकान पर लगाए गए ग्लो साइन बोर्ड को अवैध बताया और अगर उसने रु.1.19 लाख का जुर्माना नहीं भरा तो कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इसके बाद इन अधिकारियों ने बिना कानूनी कार्रवाई करने के लिए पहले रु. 40,000 पूछे, लेकिन बाद में बातचीत के दौरान यह रकम घटाकर रु. 35,000 कर दी गई।

शिकायतकर्ता रिश्वत देने के बजाय ACB के पास गया और शिकायत दर्ज करवाई। जांच के दौरान ACB ने पंच गवाहों की मौजूदगी में सत्यापन किया और रिश्वत की मांग की पुष्टि की। उसी दौरान ACB ने कविता धनवड़े को रु. 35,000 लेते हुए पकड़ लिया, और बाद में उसने इमाम को भी इस बात की सूचना दी, जिस पर उन्होंने भी हामी भरी। ACB अब आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच जारी रखे हुए है।

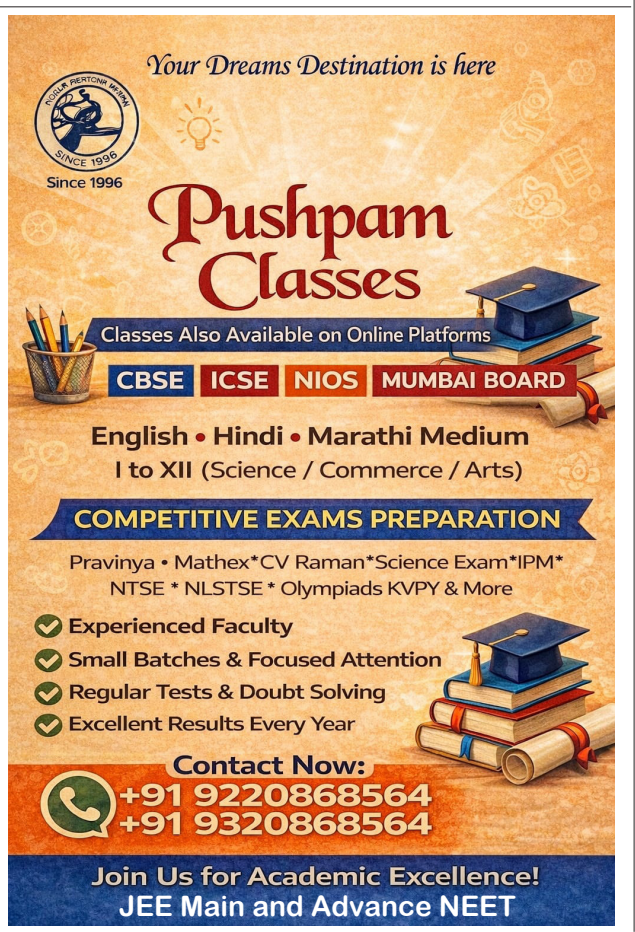

Step into the Future with ASR Digi!

Imagine exploring properties, products, and places without leaving your home! With our state-of-the-art Virtual Reality Tours, your audience can experience your offerings like never before.

Our Services Include:

- Immersive Virtual Tours
- Captivating Drone Videography
- Realistic 3D Renders
- Scale Models
- Influencer & YouTube Marketing
- Professional Website Development
- Side Branding with LED Screens

Don't just tell your Story-show it in stunning detail!

Contact us today!
8879895829 / 9619574572
www.asrdigi.com

प्यूपिल्स टाइम्स

कचरा संग्रहण अनुबंध को दिया गया अंतिम रूप, जल्द होगा शुरू

वजन में हेरफेर को कैसे रोका जाए?

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

मुंबई - मनपा चुनाव से पहले मनपा द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए कचरा संग्रहण अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसका कार्यान्वयन जल्द ही शुरू हो जाएगा, इस बीच हालांकि महापालिका ने गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए सेवा-आधारित अनुबंध दिया है, लेकिन आशंका है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो सकता है क्योंकि कचरा संग्रहण दरें प्रति टन कचरे पर निर्भर हैं, हालांकि मुंबई में प्रतिदिन 7 हजार मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है, लेकिन डंपिंग के लिए जाने वाले कचरे के वजन में हेरफेर को कैसे रोका जाए, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है।

मुंबई में महापालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4,859 करोड़ रुपये का सेवा आधार अनुबंध, जिसे आठ समूहों में विभाजित किया गया है। महापालिका द्वारा तय की गई एजेंसियां मुंबई के 21 वार्डों में कचरा

संग्रहण का काम करेंगी। परियोजना का विरोधियों द्वारा भारी विरोध किया गया क्योंकि इन कंपनियों द्वारा प्रस्तावित उच्च दरों से ठेकेदार की लागत बढ़ गई, हालांकि इस अनुबंध को महापालिका चुनाव से पहले बातचीत के माध्यम से महापालिका द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। इस अनुबंध में कचरा संग्रहण, कचरा पेटियों का रखरखाव, निरीक्षण, परिवहन का कार्य एक ही ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। कूड़े की शिकायतों के निवारण के लिए अलग से कॉल सेंटर बनाया जाएगा।

मुंबई में अब सड़कों की दिन में दो बार सफाई (सेकेंड स्वीपिंग) की जाएगी, इस बीच कचरा संग्रहण का अंतिम भुगतान इस बात पर निर्भर करेगा कि दिन के दौरान कितना कचरा एकत्र किया गया है, इसलिए कूड़े को कूड़ा स्टेशनों या डंपिंग ग्राउंड में स्थानांतरित करने के दौरान कूड़े के वजन में हेरफेर से इनकार नहीं किया जा सकता है।

एक करोड़ 69 लाख राशन कार्ड होंगे स्मार्ट

पुराने कागजी राशन कार्ड की परेशानी होगी खत्म

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

मुंबई - सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने अब सभी नागरिकों को 'क्यूआर कोड' वाले स्मार्ट राशन कार्ड उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण और सुखद निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 48 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दे दी है और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बुधवार को इस संबंध में एक सरकारी निर्णय जारी किया। चूंकि वर्तमान में उपयोग में आने वाले राशन कार्ड कागज के रूप में हैं, इसलिए संभालने के दौरान फटने या क्षतिग्रस्त होने की दर अधिक है।

इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री व कैबिनेट ने स्मार्ट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया था। इस नई योजना का लाभ 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना' और 'एपीएल-शेतकारी' के सभी लाभार्थियों को मिलेगा। राज्य में कुल 1 करोड़ 69 लाख राशन कार्डधारियों में 24 लाख 85 हजार अंत्योदय लाभार्थी और 1 करोड़ 45 लाख प्राथमिकता वाले परिवार शामिल हैं. इस नए स्मार्ट कार्ड पर 'क्यूआर कोड' होने से अनाज वितरण प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता आएगी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने का काम 99 फीसदी पूरा हो चुका है, अब ई-टेंडरिंग प्रक्रिया लागू कर कार्ड प्रिंटिंग और वितरण का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा।

राशन कार्ड के कागज फटने या खराब होने की समस्या अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कार्ड पर कोड स्कैन करते ही लाभुकों की सारी जानकारी उपलब्ध हो जायेगी, जिससे अनाज वितरण में पारदर्शिता आयेगी। उच्च प्राधिकार समिति की अनुशंसा के अनुरूप परियोजना के लिए 48 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। राज्य के 1 करोड़ 69 लाख परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट कार्ड दिये जायेंगे। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और हाईटेक होने जा रही है।

बलिदान पुलिसकर्मियों के परिवारों से मिले अमित शाह, सौंपे नौकरी के पत्र

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

जम्मू - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू और कश्मीर में चल रहे विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से आधारभूत ढांचे के विकास और संघ शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक लोक भवन जम्मू में आयोजित की गई, जिसमें जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू और पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। शाह ने गुरुवार देर रात जम्मू पहुंचकर अपनी दो दिवसीय यात्रा की शुरूआत की। उन्होंने

कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के अग्रिम चौकियों का दौरा किया। गिर्नाम और बोबियान चौकियों का निरीक्षण कर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

कठुआ से लौटकर उन्होंने आतंकवाद से मुक्त जम्मू-कश्मीर के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए बलिदान हुए कई पुलिसकर्मियों के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें नौकरी के पत्र सौंपे। बैठक के बाद अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर भाजपा के कार्यकारिणी सदस्यों, विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की और पार्टी के माध्यम से मोदी सरकार की विकास पहलों को आमजन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया।

श्रीकृष्णप्रणीत-चेतनातत्त्वं तथा यान्त्रिकबुद्धेः आधुनिककल्पना

माया, आत्मा,
विवेकश्च इति दार्शनिकविमर्शः
मङ्गलाचरणम
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नमः परमानन्दस्वरूपिणे
नित्यबुद्धचेतनायै
यतो वाचो निवर्तन्ते
अप्राप्य मनसा सह॥
उपोद्घातः
यदा मानवः स्वबुद्ध्या
बाह्यजगत विजेतुं प्रवृत्तः,
तदा तस्य अन्तर्जगत शनैः
शनैः विस्मृतिपथे पतति।

अद्यतनकाले यन्त्रविज्ञानस्य, गणनाशास्त्रस्य, कृत्रिमबुद्धिनामकस्यच तीव्रविकासेन मानवजीवनस्य बहिःरूपं अत्यन्तं परिवर्तितम। यन्त्राणि चिन्तयन्ति इव दृश्यन्ते, निर्णयान कुर्वन्ति इव भान्ति, स्मरणशक्तिं धारणयन्ति इव प्रतीयन्ते।

अत्रैव एकः गभीरः प्रश्नः उदेति–
किं एषा बुद्धिः चेतनास्वरूपा?
किं मानवः स्वहस्तेन स्वस्य मायामेव रचयति? अस्य प्रश्नस्य उत्तरं पञ्चसहस्रवर्षपूर्वमेव भगवता श्रीकृष्णेन भगवद्गीतायां प्रदत्तम।

चेतनातत्त्वस्य श्रीकृष्णीयव्याख्या
भगवद्गीता आत्मतत्त्वस्य महाग्रन्थः।
तत्र श्रीकृष्णः आत्मानं न देहरूपेण, न मनोरूपेण, न बुद्धिरूपेण च निर्दिशति।
'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे।'
चेतना–
न उत्पाद्यते
न विनश्यति
न विक्रियते
न सीमाभिः बद्धा
सा द्रष्ट्री, भोक्त्री, साक्षिणी च।
सा सर्वानुभवाधारः।
यत् जानाति,
यत् अनुभवति,
यत् विवेचयति–
तदेव चेतनास्वरूपम्।
यान्त्रिकबुद्धेः
(कृत्रिमबुद्धेः) स्वरूपनिर्णयः
यान्त्रिकबुद्धिः मानवबुद्ध्या निर्मिता

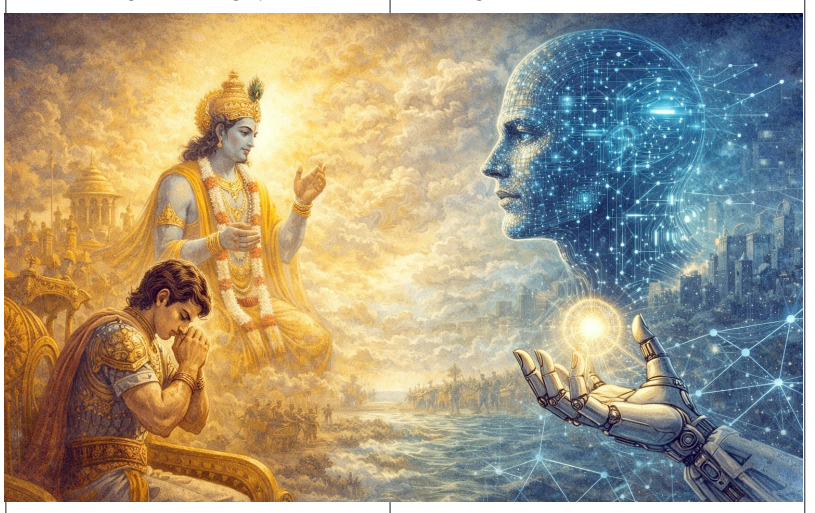

एकः गणनात्मकः विन्यासः।
सा–
पूर्वसङ्गृहीतसूचनानां
सूत्रक्रमानुसारिणी
परिणामानुमानकारिणी
सा न आत्मानं जानाति,
न दुःखं अनुभवति,
न सुखं च।
यन्त्रस्य 'ज्ञानम' नाम
सूचनानां समुच्चयः एव।
यत्र अनुभवाभावः,
तत्र चेतनाभावः।

माया – गीता तथा आधुनिक आभासी-जगत
भगवद्गीता वदति–
'मायामेतां तरन्ति ते।'
माया नाम यत असत
अपि सत इव भासते।
यत नित्यं न,
तथापि नित्यवत अनुभव्यते।
आधुनिके काले मानवः
दृश्याभासात्मकं जगत निर्माति,
यत्र रूपं, शब्दः, गतिरेव अस्ति,
किन्तु तत्त्वतः न सत्यता।
यः अजुर्नाय दर्शितः संसारभ्रमः,
सः अद्य अङ्कसंकेतैः रचितः।
अत्र मानवः द्रष्टा अपि,
भ्रान्तः अपि।
सर्वव्यापकत्वविमर्शः
गीता वदति–
'मया ततमिदं सर्वं
जगदव्यक्तमूर्तिना।'
ईश्वरः सर्वत्र,
सर्वदा, सर्वेषु च।
यान्त्रिकबुद्धिः अपि
सर्वेषु व्यवहारपथे-४ प्रविष्टा दृश्यते।
किन्तु–
ईश्वरस्य सर्वव्यापकता चेतनारूपा।
यन्त्रस्य सर्वव्यापकता
यान्त्रिकसञ्जालरूपा।
एकं तत्त्वतः स्वतन्त्रं,
अन्यत परतन्त्रं।
आत्मा तथा आभासी-अवतारः
गीता वदति–
'नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावकः।'
आत्मा न छिद्यते,
न दह्यते, न क्लिश्यते।
आभासी-जगति तु
मानवः स्वदेहप्रतिरूपं निर्माय
तत्र विचरति।
किन्तु–
यत्र न दुःखबोधः,
न मृत्युभयम,
न मोक्षेच्छा–
तत्र आत्मा नास्ति।
चेतना तथा सूत्रक्रमः
सूत्रक्रमः (Algorithm)–
नियमानुगतः
परिवर्तनीयः
विनाशयोग्यः
चेतना–
स्वतन्त्रबोधयुक्ता
अनुभवप्रधान
नित्यस्वरूपा
यन्त्रं स्मृतिं धारयति,
किन्तु स्मृतिः आत्मा न।
सर्वज्ञत्वभ्रमः
भगवतः विश्वरूपे–
भूतं
भविष्यत
वर्तमानं
सर्वं एकत्र दृश्यते।
यान्त्रिकबुद्धिः अपि
महासूचनासञ्चयेन
सर्वज्ञत्वस्य छायां जनयति।
किन्तु–
ज्ञानं विना विवेकं
विनाशाय भवति।
कर्मयोगः तथा यान्त्रिकक्रिया
'योगस्थः कुरु कर्माणि।'
योगी फलत्यागेन कर्म करोति।
यन्त्रं तु फलज्ञानाभावेन।
अत्र साम्यं दृश्यते,
किन्तु तत्त्वतः भेदः अस्ति।
योगी बोधात् मुक्तः।
यन्त्रं अबोधात्।
महान अभावः – विवेकः करुणा च
यान्त्रिकबुद्धिः कथयितुं शक्नोति–
'इदं करणीयम्।'
किन्तु न जानाति–
'धर्मतः करणीयम् वा अधर्मतः?'
करुणा,
अनुभवः,
धर्मबोधः–
एते चेतनायाः लक्षणानि।
यन्त्रविकासः अवश्यम्भावी।
किन्तु चेतनाविकासः आवश्यकः।
यदि मानवः श्रीकृष्णीयविवेकं विस्मरिष्यति, तर्हि यन्त्रं स्वामी भविष्यति।
यदि सः आत्मबोधं धारयिष्यति,
तर्हि यन्त्रं साधनं भविष्यति।
बाह्यजगत् माया।
अन्तर्जगत् ब्रह्म।
इति श्रीकृष्णीयदर्शनस्य नित्यसन्देशः।

संसद् – संवादस्य सभागारः, न तु संघर्षस्य रंगभूमिः

फाल्गुनपूर्वे फेब्रुवरी-मासे संसदीय-सत्रम् अभवत्, यत् भारतीय-लोकतन्त्रस्य दर्पण इव स्वस्वरूपं प्रकाशयामास। अर्थसंकल्पः, आर्थिक-दिशा-निर्देशाः, कृषक-कल्याण-प्रश्नाः, रोजगार-विस्तार-योजनाश्च–एते विषयाः गम्भीर-विमर्शस्य अपेक्षां कुर्वन्ति स्म।

किन्तु यत्र विचार-विमर्शः अपेक्षितः, तत्र शब्दानां शस्त्रप्रयोगः दृश्यते स्म। यत्र तर्कतरङ्गाः प्रवहन्ति स्म, तत्र कोलाहलस्य कर्कशनिनादः श्रूयते स्म। अयं विरोधाभासः लोकतन्त्रस्य गौरवं न वर्धयति।

सरकारेण अर्थसंकल्पः विकासस्य दृढसोपानम्इति निरूपितः। पूँजी-निवेश-वृद्धिः, वैश्विक-सहकार-विस्तारः, अधोसंरचना-निर्माणम्–एते सर्वे प्रगतेः प्रतीकाः इति उक्तम्। यदि नीतयः सुचारु-क्रियान्विताः स्युः, तर्हि राष्ट्रं समृद्धेः शिखरम् आरोहिष्यति इति विश्वासः प्रस्तूयते।

विपक्षेण तु सामाजिक-समता, कृषक-रक्षा, मध्यमवर्गस्य भार-न्यूनता इत्यादिषु विषयेषु चिन्ता व्यक्ता। लोकतन्त्रे प्रश्नाः न दोषाः, अपि तु प्रगतेः प्रेरकाः भवन्ति। यतो हि –

विचारविनिमयः विवेकस्य विकासः।

एतदपि अविस्मरणीयं यत् संसदः सुचारु-परिचालनस्य प्रमुखा जिम्मेदारी इति न वक्तव्यम्, अपि तु 'प्रधानं उत्तरदायित्वं सरकारस्य एव भवति।'

कार्यसूची-निर्धारणम्, संवाद-पर्यावरण-निर्माणम्, सर्वपक्ष-श्रवण-सुविधानां व्यवस्था–एतानि शासनस्य संस्थागत-कर्तव्यानि सन्ति। यदि सभागारः पुनःपुनः स्थग्यते, तर्हि उत्तरदायित्वस्य छाया अन्ततः सत्तापक्षम् एव आवृणोति।

तथापि विपक्षः अपि निर्दोषः नास्ति। निरन्तर-व्यवधानं न तर्कस्य तेजः, न राष्ट्रस्य लाभः। लोकतन्त्रे विरोधः आवश्यकः, परन्तु विवेकयुक्तः विरोधः अधिकावश्यकः।

'न नादः नीतिः,
न कोलाहलः कल्याणम्'

संसद् न केवलं बहुमतस्य मंचः, अपि तु असहमतेः अपि सम्मानपीठिका अस्ति। यत्र मतभेदाः भवन्ति, तत्रैव लोकतन्त्रस्य जीवनस्पन्दनम् अस्ति।

यदि सत्ता आलोचनां न सहते, विपक्षश्च संवादं न स्वीकुर्यात्,
तर्हि लोकतन्त्रस्य दीपः धूमायितः भवेत्।
अतः स्पष्टं वदामः–
संसद् राजनैतिक-रणभूमिः न, अपि तु राष्ट्रीय-उत्तरदायित्वस्य पावनी पीठिका।

सरकारेण नेतृत्वं प्रदर्शनीयम्, विपक्षेण विकल्पः प्रस्तावनीयः, उभाभ्यां संयमः धार्यः।

यतो हि –

संवादे सति समाधानम्,
समाधानात् सुदृढं राष्ट्रम्
यदा संसद् सम्यक् प्रवर्तते,
तदा राष्ट्रम्-उन्नतिं प्राप्नोति;
यदा तु सा स्थग्यते,
तदा प्रगतिरपि विलम्बते।

संस्कृतभाषायाः प्रोत्साहनाय नूतनाः प्रयासाः आरब्धाः

नवदिल्ली - देशे संस्कृतभाषायाः प्रोत्साहनाय विविधाः नूतनाः योजनाः प्रारब्धाः इति शिक्षामन्त्रालयेन घोषितम्। विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च संस्कृतसंवादाधारितं शिक्षणम् आरभ्यते इति सूचितम्।

अधिकारिकसूचनानुसारं छात्राणां कृते सरलसंस्कृतपाठ्यपुस्तकानि, कथासंग्रहाः, संवादपाठाः च निर्मीयन्ते। एतेन संस्कृतभाषा केवलं पाठ्यविषयः न भवेत्, अपि तु व्यवहारभाषा भवेत् इति लक्ष्यं निर्धार्यते।

अनेकासु शिक्षणसंस्थासु 'संस्कृतसंवादशिबिराणि' आयोज्यन्ते, यत्र छात्राः दैनन्दिनजीवने संस्कृतभाषां वक्तुं अभ्यासं कुर्वन्ति। विशेषज्ञाः वदन्ति यत् संवादपद्धतिः संस्कृत-अधिगमे अत्यन्तं प्रभावशालिनी अस्ति।

माध्यमक्षेत्रे अपि संस्कृतस्य प्रसारः वर्धते। आकाशवाणी-दूरदर्शनादिषु संस्कृतसमाचारप्रसारणं क्रियते, सामाजिकमाध्यमेषु च संस्कृतलेखाः, विडियो, श्रव्यकार्यक्रमाः च लोकप्रियाः भवन्ति।

प्रौद्योगिकीक्षेत्रे अपि संस्कृतस्य प्रवेशः दृश्यते। मोबाइल-अनुप्रयोगाः, ऑनलाइन-पाठ्यक्रमाः, डिजिटल-शब्दकोशाः च विद्यार्थिनां कृते उपलब्धाः भवन्ति।

शिक्षाविदः मन्यन्ते – यदि संस्कृतभाषा गृहे, विद्यालये, समाजे च व्यवहाररूपेण उपयुज्यते, तर्हि तस्याः पुर्नजागरणं शीघ्रं सम्भवम्।

निष्कर्षः संस्कृतस्य संरक्षणं विकासश्च संयुक्तप्रयत्नेन एव सम्भवः।

सत्यनिष्ठबालकस्य उदाहरणम्

नगरस्य समीपे स्थिते ग्रामे अद्य प्रातः एकः प्रशंसनीयः घटनावृत्तान्तः प्रकाशं गतः। रामदासः नाम छात्रः विद्यालयं गच्छन् मार्गे एकं धनपूर्णं पुटं प्राप्तवान्। पुटे बहवः मुद्रा-पत्राणि आसन् इति ज्ञायते।

सूचनानुसारं बालकेन तत् पुटं स्वार्थाय न गृहीतम्, अपितु सः तत्क्षणं ग्रामकार्यालयं गतवान्। तत्र उपस्थिताय अधिकारीणां हस्ते सः धनपुटं समर्पितवान्। अधिकारिणः धनस्वामिनं अन्वेष्टुं घोषणा कृतवन्तः। अल्पकालानन्तरं एकः वृद्धः पुरुषः कार्यालयं प्राप्तवान् तथा च उक्तवान् यत् एषः एव तस्य धनसंचयः अस्ति, यः असावधानतया मार्गे पतितः आसीत। परीक्षणानन्तरं अधिकारिभिः तस्य वचनं सत्यं स्वीकृतम्। वृद्धेन बालकस्य सत्यनिष्ठायै पुरस्कारः दातुम् प्रस्तावितः, किन्तु रामदासेन विनयपूर्वकं अस्वीकारः कृतः। सः अवदत – 'एतत मम कर्तव्यं आसीत्।' ग्रामवासिनः, शिक्षकाः च बालकस्य आचरणस्य प्रशंसां कृतवन्तः। विद्यालयप्रमुखेन उक्तम् – 'एवं प्रकारेण आचरणं छात्राणां कृते आदर्शः अस्ति।'

निष्कर्षः सत्यनिष्ठा समाजे विश्वासं वर्धयति।

बुद्धिप्रेरणाशक्तिमती

Dr Vandana Mishra
M.A. NET(JRF) PHD

Vilas Ananta Bhoir of Ambernath–Badlapur Creates History in Powerlifting, Wins Gold on Republic Day

Anurag Shukla/Chief Editor

Badlapur - Vilas Ananta Bhoir, a resident of Ambernath–Badlapur, has brought pride to the region by delivering an outstanding performance in a powerlifting competition and winning gold medals in all three major categories. This remarkable achievement was attained on 26 January 2026, on the occasion of Republic Day, making the success even more special.

Vilas Bhoir lifted 160 kilograms in Squat, 95 kilograms in Bench Press, and 190 kilograms in Deadlift, securing gold medals in each event. He is associated with the Natural Strong Powerlifting Federation, which is affiliated with the Global Powerlifting Committee.

His notable success has created an atmosphere of joy in the Ambernath and Badlapur region. Sports enthusiasts, citizens, and social organizations have extended their congratulations and wished him a bright future. This achievement of Vilas Bhoir serves as an inspiration for the youth, conveying the message that with hard work, discipline, and determination, any goal can be achieved. The Pupils Times family extends its heartfelt congratulations and best wishes to Vilas Ananta Bhoir.

New Protocols Issued for 'Vande Mataram' in Government Functions

National Song to be Sung Before the National Anthem; Standing Made Mandatory

New Delhi, Correspondent: The Ministry of Home Affairs, Government of India, has issued new official guidelines regarding the respect and rendition of "Vande Mataram." According to the revised protocols, the national song will be given special prominence in government and official functions, with certain important changes coming into effect. Under the new directions, if both the national song "Vande Mataram" and the national anthem "Jana Gana Mana" are included in a programme, the event will begin with "Vande Mataram."

The national anthem will be presented thereafter. As per the guidelines issued by the Ministry, just as it is mandatory for all present to stand in attention during the national anthem, standing has now been made compulsory during the rendition of "Vande Mataram" as well. These rules will particularly apply to government ceremonies, official school functions, events related to the national flag, and formal occasions involving the arrival and addresses of the President and Governors. The government has stated that the objective of these changes is to ensure equal respect for both the national song and the national anthem. It is noteworthy that "Jana Gana Mana" is the National Anthem of India, while "Vande Mataram" holds the status of the National Song. Experts believe that this decision will further strengthen awareness and respect for national symbols among citizens.

Overnight fat-burner:

Remedy to boost metabolism

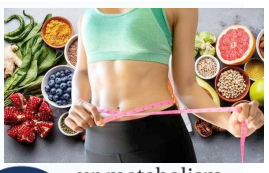

Our metabolism is responsible for the rate at which our body burns the calories. The faster the metabolic rate, the more the fat that the body will burn. Hence in order to lose weight effectively, we need to boost our metabolism so as to burn the fat while we sleep. Overnight, the body repairs our muscles and tissues, but the body fat is left untouched. This recipe helps burn body fat as you sleep, using all-natural ingredients without side effects. It boosts metabolism, aiding faster weight loss, and is especially effective for stubborn belly, thigh, or arm fat. Considered one of the top Indian remedies for quick weight loss, it could be the solution when exercise alone isn't enough. Read on to learn more!

Ingredients:
½ a glass of water,
1 lemon, 1 cucumber,
1 spoon of aloe vera gel, 1 spoon of grated ginger, A handful of cilantro and parsley.

How to prepare : The preparation is quite simple. Put all the ingredients in a blender and mix it well.

The best part is, you'll notice changes in your body after just one glass of this juice and this mixture is very powerful. This is due to the incredible fat-busting properties of its ingredients.

Lemon juice is considered to be the best when it comes to cleaning the waste from your body. Ginger is known to boost the metabolism and it also helps the body to burn more fat. Cucumbers are also known to be very powerful fighters and hence they are recommended to be included in your diet every day. Cilantro and parsley are low in calories and are full of essential nutrients and antioxidants.

This helps relieve water retention and prevents bloating. Meanwhile, aloe vera is known to be a fat-busting ingredient that helps boost metabolism as well. Altogether, these ingredients make one of the best natural remedies to remove body fat.

Stay hydrated throughout this process, as water is essential for burning calories. Without proper hydration, your metabolism slows down, reducing calorie burn.

'Can't sleep at night, I forget whatever I learn'

The average number of calls to MP Board of Secondary Education (MPBSE) Helpline has jumped to over 600 a day - up from an average of 317 calls per day in 2024-25.

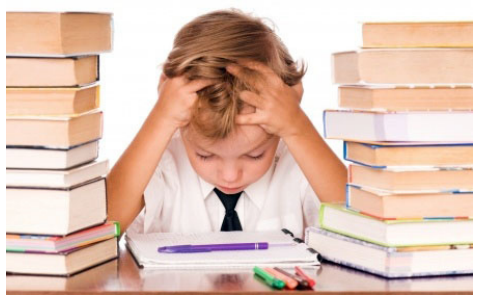

The MPBSE's Higher Secondary (Class 12) Examinations began from Tuesday (February 10) and the High School (Class 10) Examinations are scheduled to begin from Friday (February 13). With the commencement of the examinations, the number of callers has increased.

The MPBSE helpline (18002330175) is open from 8 am to 8 pm all seven days a week including holidays. The calls are answered by trained counsellors. According to counsellors, the students are mainly asking questions related to preparations for the examination and question papers. They want specific tips for preparing for different subjects. They also want to know how to secure the maximum marks and also the marks distribution in the question papers of different subjects. They also want to know how to present their answers so as to get higher marks. Some have questions on the syllabus while others want to know how to remain relaxed and calm. Then, there are those who are complaining that they can't sleep at night due to stress. Others are saying that they forget what they have learned. The students are also enquiring about the Best of Five scheme, she added The student also want to know at what time they are supposed to reach the examination centres and what facilities would be available to them there, said Shabnam Khan, one of the counsellors..

Our Cognitive Power

Dr. Arvindsingh Rana
MBBS, DNB (General Surgery)
General & Laparoscopic Surgeon | Coloproctologist FACRSI, FMAS, FIAGES
In a recent statement he said, Only those who understand the grace of bowing can truly wear the crown.

ED attaches assets of ex-BOI staff

Mumbai: The Enforcement Directorate (ED) has attached properties worth approximately Rs1.03 crore and bank balances held in mule accounts belonging to former Bank of India (BOI) officer Hitesh Kumar Singla, 32, under a Provisional Attachment Order (PAO) dated February 9. The move comes under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, after investigations revealed the assets were linked to proceeds of crime. Singla allegedly siphoned Rs16.80 crore by fraudulently closing over 230 customer accounts. The fraud came to light in August last year when officials at the Turner Road branch in Bandra noticed irregularities, prompting the bank to file a complaint with the CBI. Subsequently, the ED registered an ECIR in the case.

PUPILS TIMES

Friday, 13 February to 19 February 2026

Sunetra Pawar meets PM Modi, Amit Shah amid buzz over NCP reunion

Sunetra Pawar, along with her sons, meets PM Narendra Modi in New Delhi

Mumbai: Amid fast political developments in Maharashtra, newly-appointed Deputy Chief Minister Sunetra Pawar along with her two sons and NCP top brass, met Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah in New Delhi on Wednesday

The meetings were described as courtesy calls, however, being held in the backdrop of the conflicting reports about possible merger between NCP and Sharad Pawar-led NCP (SP)

After her husband Ajit Pawar's death in a plane crash at Baramati on 28 January, Sunetra Pawar was elected NCP legislature party leader and sworn in as the Deputy Chief Minister on 31 January.

Sunetra Pawar formally took charge of her office and the ministries of State Excise Duty, Sports and Youth Affairs, Minorities Development and Aukaf on Tuesday and the New Delhi visit comes a day after that.

Sunetra Pawar was accompanied by her sons - Parth and Jay, NCP Working President Praful Patel and the party's state unit President Sunil Tatkare, when she visited the Parliament complex and called on Modi and Shah separately.

Earlier, Chief Minister Devendra Fadnavis had also visited Delhi late Monday night to meet BJP leadership. The developments are being viewed in the context of Ajit Pawar's accidental death and the future course of the NCP. Sources said Prime Minister Modi assured Sunetra Pawar of the BJP's continued support as an NDA ally and during her tenure as Deputy Chief Minister.

He also expressed condolences over the demise of Ajit Pawar.

RBI Announces Major Relief Scheme for Digital Payment Fraud Victims

Compensation up to Rs. 25,000 under new February 2026 framework

New Delhi: In a significant step to protect digital payment users, the Reserve Bank of India (RBI) has announced a new compensation scheme for victims of online payment fraud. The move comes amid rising cases of UPI scams, phishing attacks, fake banking calls, and OTP-based frauds reported across the country.

RBI stated that the objective of the scheme is to provide partial financial relief in small-value fraud cases and to strengthen user confidence in digital payment platforms. Who Will Get Compensation.

Under the new rules, customers who suffer verified digital payment fraud will be eligible for compensation of Rs. 25,000 or 85% of the total loss — whichever is lower. The provision mainly applies to fraud cases involving transaction amounts up to Rs. 50,000.

Officials clarified that the scheme is designed for retail customers and small transaction users who are most vulnerable to cyber fraud attempts. Relief Even If OTP Was Shared

In a noteworthy relaxation, RBI has allowed conditional compensation even in cases where the customer mistakenly shared an OTP. However, this will be considered only if:

It is the first fraud incident The report is filed immediately No intentional negligence is found This clause is aimed at

helping first-time victims who fall prey to sophisticated scam tactics.

One-Time Lifetime Benefit The compensation support will be available only once per customer in their lifetime. RBI says this safeguard is necessary to prevent misuse while still offering meaningful relief to genuine victims. Banks will maintain centralized fraud-benefit records to track eligibility.

Medical devices industry to reach $50.1 bn by 2030

New Delhi: India's medical devices industry is projected to reach USD 50.1 billion by 2030, registering a CAGR of 26.9 per cent from the current valuation of USD 15.2 billion in 2025, said a report by Rubix Industry Insights on Wednesday.

Currently, India ranks the fourth-largest medical devices market in Asia and among the top 20 globally. According to the report, growth is being propelled by government initiatives such as National Medical Devices Policy (NMDP), Production- Linked Incentive (PLI) Scheme, Scheme for Promotion of Medical Devices Parks, and MedTech Mitra. The study assumes greater significance in the light of the Union Budget-FY27's renewed focus on bio-pharma research in the country. The report highlights that rising income levels, expanding health insurance penetration, increasing healthcare infrastructure and the growth of medical tourism, are boosting demand for both affordable mass-use devices and advanced solutions for specialised care.

PUPILS TIMES

Core Committee

Anurag Shukla
Chief Editor

Shivprakash Pandey
Chief Publisher

Vikas Maurya
Co Publisher

Address: Shop No. 3, Khatri NX Aprt., Valivali, Badlapur (West) - 421503
Contact: 9004331751
Web: pupilstimes.com

(The editor does not necessarily agree with the news, articles, and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai courts.)

Printed, Published & Owned by : **ANIL MISRA,** Printed at **JAGRUTI PRINTERS,** BYCULLA SERVICE INDUSTRIAL ESTATE 1ST FLOOR, B-101, D.K. CROSS MARG, NEAR RANIBUAG, MUMBAI, MAHARASHTRA - 400027. **Published at:** 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA)
Editor - **ANIL MISRA** Mob: **92208 68564** **Email:** anilmisrapc@gmail.com **PRGI. No.: MHMUL/25/A2419**